



ज़िला अदालतों का बुनियादी ढाँचा

चर्चा में क्यों?

मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा, जस्टसि ए.एम. खानवलिकर और डॉ. वाई. चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने 16 पेज के आदेश में कहा है कि देश भर में कि ज़िला अदालतों का बुनियादी ढाँचा वैटलिटर पर है और इसे बचाने की ज़रूरत है।

प्रमुख बादु

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश अखलि भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन (All India Judges Association) द्वारा बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिये सुवधाओं हेतु सन 1989 में दायर याचिका पर निरिण्य देते हुए दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा है कि "मज़बूत आधारभूत संरचना एक दृढ़ और स्थिर न्यायकि प्रणाली की धुरी है।"
- इस तरह मज़बूत बुनियादी ढाँचे के बना न्यायपालिका अपने इष्टतम सतर पर काम नहीं कर पाएगी।
- सर्वोच्च अदालत के अनुसार, देश भर की ज़िला अदालतों को नमिनलिखिति सुवधाओं से लैस किये जाने की ज़रूरत है-

- ◆ ट्रांसजेंडर के लिये अलग शौचालय
- ◆ एमबीए की डिग्री के साथ 'कोरट मैनेजरस'
- ◆ बरेल और रंग-संकेतों से युक्त चेतावनी संकेतक
- ◆ भीड़ परबंधन व्यवस्था
- ◆ शांतिगृह या क्रेच की व्यवस्था
- ◆ वादियों को सलाह देने के लिये फरंट डेस्क की सुवधि

- अदालत ने राज्य के मुख्य सचिवों को एक समतिबनाने का आदेश दिया है जिसमें अदालतों के विकास के लिये योजना बनाने हेतु एक सदस्य के रूप में विधिविभाग के सचिव भी शामिल होना चाहिये।
- यह समतिउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक अधिकारी को भी शामिल करेगी।
- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित ज़िला अदालतों में सुवधाओं को बेहतर बनाने के लिये राज्यों द्वारा तैयार स्थितिरपिट और योजनाओं की जाँच के लिये 23 अगस्त की तिथि निरिधारित की है।